देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 25.07.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं हो रही हैं सुदृढ़, कांवड़ यात्रा मार्ग पर इस बार 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
- आपातकालीन चिकित्सा सहायता– 'संजीवनी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा' से प्रदेश में अब तक 60 से अधिक जरूरतमंदों को समय पर राहत पहुंचाई गई।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारी संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए राष्ट्रीय नीति 2025 का अनावरण किया।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को अपनी परियोजनाएं, पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।
- केदारनाथ धाम तक यात्रियों की सुरक्षित और सरल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सड़क मंत्रालय सुरंग निर्माण की संभावनाएं तलाश रहा है।

संजीवनी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा

उत्तराखंड सरकार द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए शुरू की गई 'संजीवनी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा' अब तक 60 से अधिक जरूरतमंदों को समय पर राहत पहुंचा चुकी है। यह सेवा एम्स ऋषिकेश से 24 घंटे अलर्ट मोड में संचालित हो रही है।

भारत की पहली निशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा के रूप में 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई यह पहल विशेष रूप से सड़क दुर्घटना, भूस्खलन, बाढ़ और गर्भावस्था संबंधी आपात स्थितियों में कारगर साबित हुई है। अब तक हेलीकॉप्टर कुल 74 घंटे 12 मिनट की उड़ान में 60 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट कर चुका है, जिनमें 23 सड़क दुर्घटनाग्रस्त, 18 गर्भवती महिलाएं और 19 अन्य गंभीर रोगी शामिल हैं। पिछले वर्ष नवंबर में हुई अल्मोड़ा बस दुर्घटना और इस वर्ष मार्च में हुए जोशीमठ हिमस्खलन में भी इस सेवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपात स्थिति में जिलाधिकारी की मांग पर हेलीकॉप्टर सेवा प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाती है, पर उड़ान की अंतिम अनुमति मौसम और सुरक्षा मानकों के अनुसार डीजीसीए द्वारा दी जाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यह सेवा शुरू की गई है और यह देश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा देने वाले अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करती है।

स्वास्थ्य सेवाएं

इस वर्ष के कांवड़ मेले के दौरान उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सावन माह में कांवड़ यात्रा मार्ग पर 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क, त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। सीमित संसाधनों और भारी भीड़ के बीच सरकार की तैयारी प्रशंसनीय रही। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सफलता से लागू करने में मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार डॉ. आर.के. सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मेला क्षेत्र में 2 लाख 43 हजार श्रद्धालुओं को प्राथमिक और आपातकालीन सेवाएं दी गईं। यह आयोजन कुंभ 2027 के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। मेडिकल प्रबंधन के तहत 35 अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिनमें 25 विभागीय और 10 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित थे। इसके अलावा 5 कंटेनर आधारित स्थायी चिकित्सा केंद्र भी बनाए गए। सभी शिविरों की जियो टैगिंग और क्यू.आर कोडिंग की गई, जिससे श्रद्धालुओं को नजदीकी सुविधा की जानकारी आसानी से मिल सकी। उधर, पौड़ी जिले के नीलकंठ मेला क्षेत्र में 39 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। 9 मेडिकल रिलीफ पोस्ट, 7 एम्बुलेंस, 2 मोबाइल टीमें और 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई। मेले में बुखार, उल्टी–दस्त, चोटें, सर्पदंश, त्वचा रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं का सफल उपचार किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी नीति

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 जारी की। श्री शाह ने कहा कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जन समस्या निस्तारण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधमसिंह नगर के खटीमा स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान सरलीकरण, और संतुष्टि के आधार पर समयबद्ध तरीके से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर करने के प्रति गंभीर है और लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जनसमस्याएं सुनने, जनता दरबार और तहसील दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं और राज्य सरकार जटिल से जटिल जनहित के मुद्दों को भी सुलझा रही है।

शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विभागों को अपनी परियोजनाएं, पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इससे सभी परियोजनाओं की निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी, जिससे उनकी प्रगति की जानकारी विभाग और शासन दोनों को मिलती रहेगी।

सचिवालय में 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स' के संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने विभागीय सचिवों को अपनी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों की छटनी, वित्त, नियोजन और प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी और यथार्थवादी योजनाओं को ही स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने ई–ऑफिस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल को शीघ्र एकीकृत करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बताया गया कि अब तक 44 विभागों ने लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले एक हजार बीस प्रोजेक्ट्स पोर्टल पर अपलोड किए हैं।

संभावना तलाश

केदारनाथ धाम तक यात्रियों की सुरक्षित और सरल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सुरंग निर्माण की संभावनाएं तलाश रहा है। कालीमठ घाटी के चौमासी से लिनचोली तक प्रस्तावित इस सुरंग को लेकर कंसल्टेंट से सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है, जिसमें इसे प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।

गौरतलब है कि 2013 की आपदा के बाद से गौरीकुंड–केदारनाथ पैदल मार्ग मुख्य यात्रा मार्ग बना हुआ है, लेकिन यह मार्ग वर्ष 2023 की अतिवृष्टि में कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद वैकल्पिक मार्गों जैसे चौमासी–खाम बुग्याल और त्रियुगीनारायण–तोषी का सर्वे भी कराया गया। इसी कड़ी में अब सुरंग निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि कालीमठ घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही चुन्नी बैंड से कालीमठ तक 16 किलोमीटर डबल लेन सड़क और कालीमठ से सोनप्रयाग को जोड़ने वाली सात किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। इन योजनाओं के पूरी होने पर केदारनाथ यात्रा का संचालन पहले से अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाएगा।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में पूंजीगत व्यय और केंद्र व बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री बर्द्धन ने सभी विभागों को सितंबर तक कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने और पूंजीगत व्यय की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 14 हजार 763 करोड़ के कुल पूंजीगत बजट में से अब तक 2 हजार 215 करोड़ जारी हुए हैं और 1 हजार 49 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी बजट प्रस्ताव 15 अगस्त तक भेज दिए जाएं और विभागीय सचिव नियमित बैठकें करें ताकि तय लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

उन्होंने उद्यान विभाग को कोल्ड चेन, ऑफ सीजन उत्पादन और पॉलीहाउस परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए, जबकि कृषि विभाग को बायो फेंसिंग और चेन लिंक फेंसिंग के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था के साथ अलग हेड बनाने को कहा गया।

बैठक में दुग्ध विकास विभाग को आंचल ब्रांड के उत्पाद बढ़ाने और गन्ना विकास विभाग को चीनी मिलों के मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए ताकि समय पर उत्पादन शुरू हो सके।

कार्यशाला

नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा देहरादून में ' उत्तराखंड के लिए कार्बन क्रेडिट संभावित अवसर ' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य हरित उत्तराखंड की दिशा में कार्बन क्रेडिट के अवसरों की पहचान और संभावनाओं पर चर्चा करना था।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रमुख सचिव, नियोजन, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम् ने कहा कि सभी विभागों को कार्बन क्रेडिट तंत्र की जानकारी होनी चाहिए ताकि राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो और इससे जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50 प्रतिशत और 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्थागत उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुबुद्धि ने स्वैच्छिक कार्बन विपणन के लिए विशेषज्ञों की मदद से प्रस्ताव तैयार करने और स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए जाने का सुझाव दिया।

केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण प्रकोष्ठ के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत ने कहा कि वन आवरण, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक कृषि को प्राथमिकता देकर कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने विभागीय क्षमताओं के विकास और ईको सिस्टम सेवाओं के लिए विश्वसनीय डाटा पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। सभी समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है – पहले चरण में 68 प्रतिशत मतदान। राष्ट्रीय सहारा लिखता है – गांव की सरकार चुनने को बरसे वोट। अमर उजाला का शीर्षक है– मतदाताओं में दिखा लोकतंत्र के उत्सव का उत्साह।

सरकार ने राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। अमर उजाला समाचार पत्र के अनुसार– इक्कासी दशमलब सात दो करोड़ की विकास योजनाओं के लिए सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति।

उत्तराखंड के गोल्ज्यू देवता के पर्यटन विकास की ख़बर लगभग सभी समाचार पत्रों में है। दैनिक जागरण का शीर्षक है– 15 दिन में गोल्ज्यू देवता कॉरिडोर मास्टर प्लान हो जाएगा तैयार।

उत्तरांखड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र की ख़बर है – उत्तराखंड चयन आयोग ने जारी किया भर्ती का कलेंडर।